लंदन में ईंटों से बनी कई पुरानी इमारतें की खिड़कियों के नीचे ''ऐन्शन्ट लाइट्स'' लिखा हुआ है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एल्बेमार्ल वे पर बने घरों की पिछली खिड़कियां। लंदन के अलावा डॉरसैट, कैंट व इंगलैण्ड में कई जगह ये साइन देखे जा सकते हैं। असल में ''ऐन्शन्ट लाइट्स'' और ''राइट टु लाइट'' एक ब्रिटिश प्रॉपर्टी लॉ है, जो गृह स्वामी को खिड़की से प्राकृतिक रौशनी प्राप्त करने का अधिकार देता है। अगर एक घर की किसी भी खिड़की से 20 साल से निर्बाध रुप से प्राकृतिक रौशनी आ रही है तो उस व्यक्ति को ऐन्शन्ट लाइट्स का अधिकार मिल जाता है। ऐसे में समीपवर्ती भूखण्ड का स्वामी बिल्डिग बनाकर, दीवार उठाकर या पेड़ लगाकर उस रौशनी को बाधित नहीं कर सकता। पूर्व में जिन लोगों के पास राइट टु लाइट होता था वो प्रकाश में बाधा पहुंचाने के नाम पर पड़ौसी पर केस कर देते थे और जीत भी जाते थे। कॉलिन्स डिक्शनरी ऑफ लॉ के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को लगता था कि उसे पूर्व की तरह निर्बाध रुप से प्रकाश नहीं मिल रहा है तो वह पड़ौसी पर केस कर सकता था, लेकिन रौशनी की मात्रा कितनी हो यह स्पष्ट नहीं था। इससे इस क्षेत्र में कई विशेषज्ञ व विशिष्ट गवाह पैदा हो गए, जो बताते थे कि रौशनी पर्याप्त है या नहीं और कोर्ट उन पर भरोसा भी करता था। यह कानून 1663 में बना था पर इसका वर्तमान स्वरुप प्रिस्क्रिप्शन एक्ट 1832 पर आधारित है।

राहुल गांधी से चौथी बार भी लंबी पूछताछ हुई

ई.डी ने मंगलवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया

नई दिल्ली, 20 जून। नैशनल हैरल्ड मामले में पिछले सप्ताह लगातार तीन दिन की पूछताछ के बाद सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ई.डी. ने फिर पूछताछ की। उन्हें मंगलवार को फिर पूछताछ में शामिल होने को कहा गया है।

राहुल गांधी सी.आर.पी.एफ. जवानों की ''जेड प्लस' श्रेणी की सुरक्षा के साथ सुबह 11 बजकर करीब पांच मिनट पर मध्य दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित ई.डी. मुख्यालय पहुंचे थे। एक दिन पहले ही राहुल गांधी का 52वां जन्मदिन था। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सोमवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय के आसपास पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को भारी संख्या में तैनात किया गया है और धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। राहुल गांधी करीब तीन बजकर 30 मिनट पर लंच के लिए ई.डी. दफ्तर से बाहर निकले और लगभग एक घंटे के बाद फिर ई.डी. कार्यालय पहुंचे थे।

पिछले सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लगातार तीन दिन ई.डी. के अधिकारियों ने 52 वर्षीय राहुल गांधी से 30 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी, जिस दौरान धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पी.एम.एल.ए.) के तहत उनके बयान दर्ज किये गए थे। गौरतलब है कि, राहुल गांधी को गत शुक्रवार को फिर से ई.डी. के समक्ष पेश होना था, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने अपनी मां सोनिया गांधी के बीमार होने के कारण ई.डी. के जांच अधिकारी को पत्र लिख कर उन्हें शुक्रवार (17 जून) के लिए निर्धारित पूछताछ से छूट देने का अनुरोध किया था। ई.डी. ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था और 20 जून को पेश होने के लिए कहा था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कोविड-19 से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ई.डी. ने सोनिया गांधी को इसी मामले में 23 जून को तलब किया है। समझा जाता है कि 'यंग इंडियन' की स्थापना, 'नैशनल हैरल्ड' के संचालन और असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (ए.जे.एल.) को कांग्रेस द्वारा दिए गए कर्ज व मीडिया संस्था के भीतर धन के हस्तांतरण से जुड़े सवाल राहुल गांधी से पूछे गए हैं। 'यंग इंडियन' के शेयरहोल्डर में सोनिया गांधी व राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कुछ अन्य नेता शामिल हैं।

- **सोनिया गांधी को भी सोमवार को अस्पताल से छुट्टी मिली अब देखना है कि, मैडिकल आधार पर उन्हें पूछताछ से कुछ दिनों की छूट मिलेगी अथवा नहीं**
- **पिछले सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लगातार तीन दिन ईडी के अधिकारियों ने 52 वर्षीय राहुल गांधी से 30 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।**
- **सोमवार को भी राहुल गांधी से करीब 7 से 8घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई, इस तरह उनसे कुल मिलाकर 37 से 38 घंटों की पूछताछ हो चुकी है।**

अग्निपथ स्कीम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बार हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश की कहानी की गहराई में जाकर ही, असलियत मालूम पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के चुनावों में भाजपा के विधायकों की संख्या में 57 की कमी आ गई, जबकि सपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 64 सीटें ज्यादा मिलीं। इसलिये यह मान लेना गलत होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में किसान आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं रहा। भाजपा संगरूर, आज़मगढ़ तथा रामपुर के तीन लोकसभा चुनाव हार सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता जिन दिनों शिखर पर थी, उस समय ये सीटें परम्परानुसार विपक्ष के पास रहीं। किन्तु इन सीटों पर जीत का अंतर ही यह तय करेगा कि अग्निपथ योजना के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता प्रभावित हुई है या नहीं।

जहाँ किसान आन्दोलन का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा था, वहीं युवा-आन्दोलन अधिकांशतः नेतृत्व विहीन है तथा इसलिये उनके साथ समझौता वार्ता कर पाना भी सरकार के लिये मुश्किल है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ज्यादातर अँधेरे में तीर चलाते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की है, जैसे- भर्ती की उम्र बढ़ाना तथा अग्निवीरों को अद्धसैनिक बलों में 10 प्रतिशत आरक्षण देना। अग्निपथ भर्ती योजना के अगले माह शुरू होने के साथ ही यह सम्भव है कि बहुत से युवा भर्ती केन्द्रों की ओर उन्मुख हो जायेंगे। लेकिन, भाजपा को असली और बड़ा डर यह है कि युवा, जो प्रधानमंत्री के जबरदस्त एवं भावुक समर्थक हैं, भाजपा से दूर छिटक सकते है।

पवार फारूख ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बाते करते हैं कि भाजपा आर.एस.एस. गठजोड, जो संविधान को कमज़ोर कर रहा है, का मुकाबला करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा।

वर्ष 2017 में भी विपक्षी खेमा गोपाल कृष्ण गांधी को प्रत्याशी बनाना चाहता था, पर एन.डी.ए. ने रामनाथ कोविंद को प्रत्याशी बना दिया तो विपक्ष को पुनर्विचार करना पडा और कोविंद की ही तरह दलित नेता मीरा कुमार को विपक्ष ने प्रत्याशी बनाया।

'कुछ परिवर्तन शुरुआत में बुरे लगते हैं, लेकिन वक्त आने पर देश को बड़ा फायदा पहुँचाते हैं'

प्रधानमंत्री मोदी की यह टिप्पणी को इशारों-इशारों में अग्निपथ योजना का समर्थन है

नई दिल्ली, 20 जून। देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर छिड़े विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ फैसले और सुधार भले ही शुरुआत में खराब लगते हैं, लेकिन लंबे वक्त में उनसे देश को फायदा होता है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारों-इशारों में यह टिप्पणी अग्निपथ स्कीम को लेकर की है।

उन्होंने कहा कि, कई फैसले और सुधार तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय में उसके लाभ देश अनुभव करता है। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे कई सेक्टर्स को देश के युवाओं के लिए खोल दिया है, जिनमें दशकों तक सरकार का ही एकाधिकार था। आज हम देश के युवाओं से कह रहे हैं कि सरकार ने जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बनाई हैं, उनमें अपने विजन और प्रतिभा को टैस्ट करें। हम दुनिया के साथ तभी मुकाबला कर पाएंगे, जब सभी को समान अवसर दिए जाएं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु की विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जिन कामों को 40 साल पहले पूरा हो जाना था, वे आज तक लंबित हैं और अब ये मेरे हिस्से आए हैं। आप लोगों ने मुझे मौका दिया है और अब मैं समय गंवाना नहीं चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब आसपास के इलाके रैपिड रेल से जुड़ जाएंगे तो उससे बेंगलुरु में जाम समेत तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा नैशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज का हमने जो शिलान्यास किया है, उनके निर्माण के बाद बड़ी संख्या में गाड़ियों को बेंगलुरु आना ही नहीं पड़ेगा। इससे सफर भी आसान होगा और बेंगलुरु की व्यवस्था भी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि बीते 8 सालों में हमने रेलवे के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। अब भारतीय रेल तेज भी है, स्वच्छ भी है और आधुनिक भी हो रही है। इसके अलावा सुरक्षित भी है और सिटिजन फ्रेंडली भी हो रही है। हमने देश के उन हिस्सों में भी रेल को पहुंचाया है, जहां इसके बारे में सोचना तक मुश्किल था। कर्नाटक में भी 1,200 किलोमीटर से ज्यादा की रेल लाइन या तो नई बनी है या फिर विस्तार हुआ है। अब हवाई यात्रा और एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं अब रेलवे भी दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेंगलुरु के एम. विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन पर तो लोग पर्यटन के लिए जाते हैं। यहां तक कि युवाओं में तो सेल्फी की होड़ रहती है। करोना के समय बेंगलुरु में बैठे युवाओं ने पूरी दुनिया को संभालने में मदद की है। बेंगलुरु ने दिखा दिया है कि यदि सरकार अवसर दे तो भारत का युवा क्या नहीं कर सकता है। बेंगलुरु देश के युवाओं के सपनों का शहर और इसके पीछे उद्यमशीलता और इनोवेशन है। बेंगलुरु उन लोगों को अपना माइंडसेट बदलने की सीख भी देता है, जो अभी भी भारत के प्राइवेट सेक्टर को भद्दे शब्दों से संबोधित करते हैं। देश की शक्ति को करोड़ों लोगों के सामर्थ्य को सत्तावादी मानसिकता के लोग कमतर आंकते हैं। 21वीं सदी का भारत वेल्थ क्रिएटर्स और जॉब क्रिएटर्स का है। इस ताकत को प्रमोट करने के लिए जो प्रयास बीते 8 सालों में हुए हैं, उनकी चर्चा तो होती है, लेकिन बहुत सीमित दायरे में होती है। भारत में खेती के बाद सबसे बड़ा सेक्टर एम.एस.एम.ई. है। लेकिन हमारे यहां इसकी परिभाषा ही ऐसी रखी गई थी कि वे खुद का विस्तार करना चाहते थे तो उनका नुकसान होता था। इसलिए वे खुद को छोटे उपक्रम की ओर ले जाते थे। ऐसे में हमने उसकी परिभाषा को ही बदल दिया ताकि वे अपना विस्तार कर सकें।

- **प्रधानमंत्री मोदी ने बैंगलुरु में करीब 39 हजार करोड़ रु. की विकास परियोजनाओं के उद्घघाटन के वक्त यह बात कही।**

थलसेना ने अग्निपथ भर्ती की अधिसूचना जारी की

6 कैटिगिरी में अग्निवीरों की भर्ती की जायेगी

नई दिल्ली 20 जून (वार्ता)। तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती से संबंधित अग्निपथ योजना के देशव्यापी विरोध के बीच सेना ने आज इस योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी।

यह अधिसूचना सोमवार को सेना की वेबसाइट पर जारी की गयी है और इसमें अग्निवीरों की भर्ती से संबंधित सेवा शर्तों तथा भर्ती रैलियों के बारे में जानकारी दी गयी है।

अधिसूचना के अनुसार जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, क्लर्क, स्टोर कीपर और ट्रेडमेन आदि की भर्ती प्रक्रिया आगामी जुलाई से शुरू हो जायेगी।

सेना की योजना है कि आगामी अगस्त के पहले पखवाड़े में अग्निवीरों की भर्ती के लिए पहली भर्ती रैली का आयोजन किया जाना है। इसके बाद उम्मीदवारों का शारीरिक और चिकित्सा परीक्षण के बाद उनकी लिखित परीक्षा ली जाएगी। सेना में अग्निवीरों की भर्ती दो चरण में की जाएगी। पहले चरण में आगामी दिसंबर के पहले सप्ताह में 25000 तथा अगले वर्ष 23 फरवरी तक दूसरे चरण में 21000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी।

नौसेना और वायु सेना की ओर से भी इसी सप्ताह अग्निवीरों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की जायेगी।

- **अधिसूचना के अनुसार 6 कैटिगिरी में सेना की जनरल ड्यूटी, टैक्निकल स्टाफ, क्लर्क, स्टोर कीपर और ट्रेडमैन आदि की भर्ती प्रक्रिया आगामी जुलाई से शुरू हो जायेगी।**
- **सेना में अग्निवीरों की भर्ती दो चरण में की जाएगी। पहले चरण में आगामी दिसंबर के पहले सप्ताह में 25000 तथा अगले वर्ष 23 फरवरी तक दूसरे चरण में 21000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी।**

जनरल रावत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्य विपक्षी पार्टी के नेताओं पर लाठीचार्ज किया। माकन ने कहा कि सेना में नियमित भर्ती की जगह अग्निपथ योजना को थोपने का प्रयास देश के पहले चीफ ऑफ डिफैंस स्टाफ बिपिन रावत का अपमान है, वे चाहते थे कि सेना का सबसे छोटी रैंक का जवान, जो 17 साल में रिटायर हो जाता है, 58 साल तक सेवा में रहे, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि, अग्निपथ योजना में चार साल की सेवा के बाद युवा को बहुत कम उम्र में ही रिटायर कर दिया जाएगा। ''नो रैंक-नो पैंशन'' की यह योजना स्व.जनरल रावत की सोच के खिलाफ है। रावत ने 10 नवम्बर 2020 को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कर्नल रैंक की सेवा निवृति आयू 57 वर्ष, ब्रिगेडियर व समकक्ष की 58 वर्ष और मेजर जनरल व समकक्ष की आयू 59 वर्ष करने की बात कही गई थी।

'जेल में कैद एक साधारण...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लाखों लोगों का है। इस प्रकार के भेदभाव के बारे में निर्णय नहीं किया गया है, इसलिये हम इसकी और गहराई में जायेंगे।'' न्यायमूर्ति रविकुमार ने कहा, ''इस महत्वपूर्ण प्रश्न को मद्देनजर रखते हुये, हम यह कह रहे हैं कि इस प्रश्न पर और अधिक चिन्तन-मनन की जरूरत है।'' न्यायमूर्ति धूलिया ने तर्क दिया, ''एक व्यक्ति निर्वाचित तो हुआ है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। यह कुछ अलोकतांत्रिक है। हमने अभी पक्का निर्णय नहीं लिया है। लेकिन यह कुछ अलोकतांत्रिक तो है।''

इसलिये, शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी करने की कार्यवाही तो की, लेकिन कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिये।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ''दलीलों में यह बात सामने आई कि धारा 62 (5) की व्याख्या को लेकर, विचारों और दृष्टिकोणों में टकराव तो है। इसलिये हम इस पर विस्तृत सुनवाई करेंगे। लेकिन कोई अंतरिम राहत नहीं दी जायेगी।''

देशमुख, जो न्यायिक हिरासत में हैं, ई.डी. द्वारा की गई जाँच में, भ्रष्टाचार के एक मामले के मुख्य आरोपी हैं। जब एक अदालत निर्देशित जाँच के बाद, जब सैन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सी.बी.आई.) ने एफ.आई.आर. दर्ज कराई उसमें भी इन्हें मुख्य आरोपी बताया गया था। मलिक भी प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पी.एम. एल.ए.) के तहत एक मनी लॉन्डरिंग केस, जिसमें अन्डरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी लिप्त है, से कथित रूप से जुड़े होने के कारण इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। ये दोनों पूर्व मंत्री इस आधार पर उच्च न्यायालय गये थे कि चूँकि वे विधानसभा सदस्य हैं, इसलिये उन्हें विधान परिषद के चुनावों में वोट देने का अवसर दिया जाना चाहिये।

इन दोनों वादियों का कहना था कि उच्चन्यायालयों के पास ऐसे व्यापक विवेकाधीन अधिकार हैं कि वे कैदियों द्वारा चुनावों में वोट डालने के विषय में रिप्रजेन्टेशन ऑफ पीपुल एक्ट की धारा 62 (5) के तहत कानूनी प्रतिरोध को दरकिनार कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय में वादियों की तरफ से प्रस्तुत हुई वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने दलील दी कि एम.एल.सी. के चुनावों में इन दोनों को मतदान से रोकना उन सभी मतदाताओं के अधिकारों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, जिन्होंने इन दोनों विधायकों को चुना था।

उन्होंने कहा, ''जनता ने मुझे (चुनकर) विधानसभा में भेजा है। मैं उनकी पसंद तथा विधानसभा के निर्णयों के मामले में उनका प्रतिनित्व करती हूँ। अगर मुझे वोट देने के मेरे अधिकार से वंचित किया जाता है, तो जिन लोगों ने मुझे वोट दिये थे, उनका अधिकार भी छीना जा चुका होगा।''

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपस्थित हुये सॉलिसिटर जनरल (एस.जी) तुषार मेहता ने कहा कि धारा 62 (5) के तहत, सम्बंधित विषेध या प्रतिरोध विधायकों पर भी लागू होता है।

एस.जी. ने कहा, ''यह निषेध विधायकों पर भी लागू होता है। कुछ तर्काधारित प्रतिबंधों की कसोटी पर तो मौलिक अधिकार तक में कटौती की जा सकती है।'' अरोड़ा ने जवाब दिया, ''जेल में बंद किसी अपराधी एवं किसी विधायक के बीच फर्क होता है। अदालत को यह विभेदीकरण करना ही चाहिये तथा सबको एक ही लाठी से नहीं हाँका जा सकता।'' अदालत ने कहा कि अदालत ऐन वक्त पर कोई राहत नहीं दे सकती, लेकिन अदालत इस कानून का परीक्षण करने, इसकी गहराई में जाने के लिये सहमत हो गई। न्यायमूर्ति रवि कुमार ने कहा, ''प्रथम दृष्टया, अगर आप पुलिस हिरासत में हैं, तो आप (वोट देने के) हकदार नहीं हैं। यहां आप न्यायिक हिरासत में है।'' न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा, ''आप धारा 62 को पढ़ें। कानून कोई फर्क नहीं करता। क्या कोई कानून ऐसा अंतर करता है। हम इस प्रकार की चीजों में छल-कपट नहीं कर सकते। काश ! आपने हमें कुछ और समय दिया होता।'' किन्तु उच्च न्यायालय के एकल जज, न्यायमूर्ति एन.जे. जमादार ने उनकी याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि अदालतें साधारणतः उस समय तक, विधानसभा सदस्यों को विधान परिषद के चुनावों में वोट डालने के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती तथा अनुमति प्रदान नहीं कर सकतीं, जब तक कि ऐसे बहुत से विधानसभा सदस्य इसलिये जेल में न डाल दिये गये हों कि उन्हें इस बहाने वोट डालने से रोका जा सके।

अमेरिका में एक सार्वजनिक प्रोग्राम के दौरान फिर गोलीबारी

वाशिंगटन, 20 जून (वार्ता)। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डी.सी. में हुई गोलीबारी में एक नाबालिग की मौत हो गई है और एक पुलिस अधिकारी समेत कई अन्य घायल हो गए हैं।

गोलीबारी की घटना रविवार को स्थानीय समयानुसार शाम करीब छह बजे मोएचेला संस्कृति कार्यक्रम के सिलसिले में एक 'अनपरमिटेड इवेंट' में हुई।

डी.सी. विभाग ने ट्विटर पर कहा,मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग (एम.पी.डी.) 14वीं और यू स्ट्रीट, एन.डब्ल्यू. के क्षेत्र में एक गोलीबारी की घटना पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इस घटना में एक एम.पी.डी. अधिकारी सहित कई लोगों को गोली मार दी गई है।

फॉक्स न्यूज ने एम.पी.डी. के एक प्रवक्ता के हवाले से कहा कि मोचेला के एक कार्यक्रम में चार लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है।

मुठभेड़ में चार आतंकी मारे गये इनमें एक पाकिस्तानी भी शामिल

श्रीनगर, 19 जून (वार्ता)। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और कुलगाम जिलों में रविवार को सुरक्षा बलों तथा आतंकवादियों के बीच हुई अलग-अलग मुठभेड़ में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक संदिग्ध पाकिस्तानी समेत चार आतंकवादी मारे गये।

पुलिस ने आज यहां बताया कि उत्तर कश्मीर के सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा में एक पाकिस्तानी समेत दो आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि कुपवाड़ा में मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब पुलिस और सेना की 28 राष्ट्रीय राइफल्स (आर.आर.) की संयुक्त टीम ने जिले के लोलाब इलाके में गिरफ्तार आतंकवादी शौकत अहमद शेख के खुलासे पर आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया। पुलिस ने कहा कि जैसे ही सुरक्षा बलों ने ठिकाने की तलाशी शुरू की, वहां छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरु कर दी। जवाबी कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा का एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। मुठभेड़ जारी है।

पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर विजय कुमार ने ट्वीट कर कहा,मारे गए आतंकवादी की पहचान एक पाकिस्तानी के रूप में की गई है।

महात्मा गांधी के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कृष्ण गांधी (77), पूर्व राजनयिक एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल हैं, सोमवार को शरद पवार (81) तथा डॉ. फारूक अब्दुल्ला के बाद, ऐसे तीसरे ऐसे नेता बन गए, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनसे बेहतर अन्य कई ऐसे लोग हैं, जो राष्ट्रीय सर्वसम्मति पैदा कर सकते हैं। पवार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पिछले बुधवार को बुलाई गई 17 पार्टियों की एक मीटिंग में कह दिया था कि इसके लिये उन पर निर्भर न रहा जाये क्योंकि वे अभी और राजनैतिक पारियाँ खेलना चाहते हैं। इसके बाद, ममता ने डॉ. फारूक अब्दुल्ला एवं गोपाल गांधी के नामों की सलाह दी, लेकिन इस क्षण की स्थिति यह है कि विपक्ष के पास कोई प्रत्याशी नहीं है। सत्तारूढ़ भाजपा ने यहाँ बुधवार विपक्ष की मीटिंग के लिए सर्वसम्मति हेतु कुछ और नेताओं के नाम बताये, लेकिन भाजपा ने अपने उम्मीदवार का नाम उजागर नहीं किया। क्या भाजपा वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है, को ही दोहरायेगी?

डॉ. अब्दुल्ला ने शनिवार को इस पद की दौड़ में स्वयं को अलग कर लिया था और अब गोपाल गांधी भी इस दौड़ से अलग हो गये हैं। ज्ञातव्य है कि गोपाल गांधी पाँच साल पहले उप राष्ट्रपति पद की दौड़ में एम. वैंकय्या नायडू से पराजित हो गये थे। इस समय चल रहे नामांकन 29 जून तक चलेंगे तथा 2 जुलाई तक नाम वापस लिये जा सकेंगे।

'कुछ देशों ने भारत के खिलाफ साइबर क्राइम आर्मी बना रखी है'

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, साइबर क्राइम आने वाले वक्त में देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगा

नई दिल्ली, 20 जून (वार्ता)। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि, कुछ देशों ने भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए साइबर आर्मी बना रखी है लेकिन सरकार की संबंधित ऐजेन्सियां इस खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह चौकन्नी रहती हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को विज्ञान भवन में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि, हम अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं।

अमित शाह ने कहा कि आज के युग में साइबर सुरक्षा के बिना देश के विकास की कल्पना करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, अगर हम साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करते हैं, तो हमारी यही ताक़त हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। इसीलिए डिजिटल रिवॉल्यूशन के ज़माने में साइबर सुरक्षा की चुनौतियां और उनके समाधान को ढूंढने और हर व्यक्ति तक साइबर सुरक्षा की जानकारी पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा को देश के पिछड़े से पिछड़े इलाक़े से लेकर हर हिस्से तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से साइबर स्वच्छता, साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए उपाय, अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल को लोकप्रिय बनाना, साइबर वित्तीय अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन नंबर को लोकप्रिय बनाना जैसे अनेक क़दमों के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया गया है। शाह ने कहा , वर्ष 2012 में 3377 साइबर क्राइम रिपोर्ट किए गए थे और 2020 में रिपोर्टिंग की संख्या 50 हज़ार तक पहुंची है,2020 में हर दिन 136 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए, प्रति एक लाख जनसंख्या पर साइबर अपराधों की संख्या में भी चार वर्षों में 270 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 2016 में यह 1 थी और 2020 में यह बढ़कर 3.7 हो गई। ये बताता है कि ये वृद्धि आने वाले समय में कितनी बड़ी चुनौती बनने वाली है। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल तीन साल पहले लॉंच किया गया जिस पर अब तक अलग-अलग प्रकार की 11 लाख से ज़्यादा शिक़ायतें दर्ज की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया क्राइम की भी दो लाख से ज़्यादा शिक़ायतें दर्ज की जा चुकी हैं। ये मात्रा दिन-प्रतिदिन बढ़ने वाली है क्योंकि भारत में आज 80 करोड़ भारतीयों की ऑनलाइन मौजूदगी है और 2025 तक इस संख्या में लगभग 40 करोड़ की वृद्धि होने का अनुमान है।

कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह सचिव सहित गृह मंत्रालय और केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। शाह ने देश में डिजिटल क्रांति का उल्लेख करते हुए कहा कि साइबर सुरक्षित देश की कल्पना में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसलिए इसके बारे में जनजागरूकता फैलाना भी उतना ही जरूरी है क्योंकि जागरूकता के बिना इसका उपयोग नहीं हो सकता।

- **गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, वर्ष 2012 में 3377 साइबर क्राइम रिपोर्ट किए गए थे और 2020 में रिपोर्टिंग की संख्या 50 हज़ार तक पहुंच गई है, 2020 में हर दिन 136 साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए, प्रति एक लाख जनसंख्या पर साइबर अपराधों की संख्या में भी चार वर्षों में 270 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।**

'कोविड-19 की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

का अधिग्रहण कर लिया और यहां की भयभीत जनता को वृहद रूस शामिल कर लिया और इस पर किसी ने भी कोई सवाल खड़ा नहीं किया तो क्या होगा। क्या इससे शांति स्थापित होगी?

-क्रमशः

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908